कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

संगठनात्मक गतिविधियां : सदस्यता अभियान

भाजपा ने 31 मार्च तक लक्ष्य–प्राप्ति का संकल्प किया..... 7

सरकार की उपलब्धियां : आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण से बंधी उम्मीदें..... 10
अब तीव्र विकास का दौर..... 11
चौदहवां वित्त आयोग..... 13

वैचारिकी : पं. दीनदयाल उपाध्याय

हमारी राष्ट्रीयता..... 14

श्रद्धांजलि

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले..... 16

बजट 2015–16

रोजगारपरक, विकासोन्मुखी बजट..... 17
बजट गरीब हितैषी और वृद्धि अनुकूल है 20
'गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को समर्पित बजट''..... 21

रेल बजट 2015–16

आम लोगों को राहत देने वाला है रेल बजट..... 23
यह रेल बजट 'यात्री बजट' है 24

संसद में बहस

राष्ट्रपति अभिभाषण पर लोक सभा में धन्यवाद प्रस्ताव/ –नरेन्द्र मोदी..... 27

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को

राम नवमी

की हार्दिक शुभकामनाएं!

सीखने की उम्र

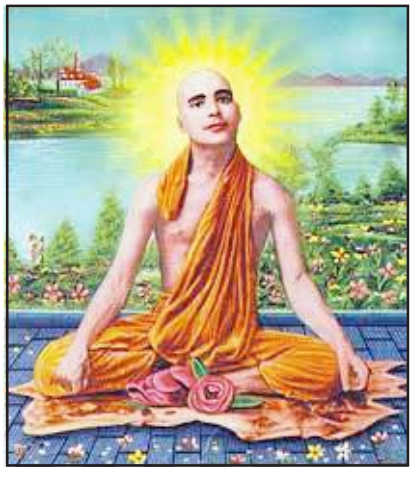

स्वामी रामतीर्थ पहली बार विदेश यात्रा पर निकले थे। जिस जहाज से वे यात्रा कर रहे थे, उसी में एक 90 वर्षीय जर्मन से उनकी मुलाकात हुई। वह बुजुर्ग चीनी भाषा सीख रहे थे। इस उम्र में उन्हें एक नई भाषा सीखते देख स्वामी रामतीर्थ को बेहद आश्चर्य हुआ। चीनी एक कठिन भाषा मानी जाती थी। उसमें पांडित्य हासिल करने के लिए कम से कम 10-15 साल का अभ्यास जरूरी था।

स्वामी रामतीर्थ कई दिनों तक उस बुजुर्ग को गौर से देखते रहे। वह नई भाषा सीखने में इस कदर मशगूल रहते कि घंटों नजर उठाकर नहीं देखते थे। एक दिन रामतीर्थ ने जिज्ञासावश उनसे पूछ ही लिया- 'महाशय, आप इस पकी उम्र में एक नई भाषा सीखने में क्यों अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं आप कब इसे सीखेंगे और कब इसका उपयोग कर पाएंगे।'

उनका यह सवाल सुनकर जर्मन बुजुर्ग ने जवाब दिया- 'किस उम्र की बात करते हैं आप? मैं काम में इतना व्यस्त रहा हूं कि कभी अपनी उम्र का हिसाब ही नहीं रख पाया। चूंकि अभी सीख ही रहा हूं, इसलिए अब तक बच्चा हूं। जहां तक मेरी मौत का सवाल है, तो वह तो पैदा होने के बाद से ही मेरे सामने खड़ी थी। अगर उसका ही लिहाज रखता रहता तो आज तक मैं कुछ भी नहीं सीख पाता।'

बुजुर्ग की सीखने की गहरी लगन से स्वामी रामतीर्थ बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटने पर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने इस अनूठे अनुभव के बारे में बताया और कहा कि हर इंसान को जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने का उम्र से कोई रिश्ता नहीं है।

संकलनः प्रदीप कुमार

(नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय

राष्ट्र मंदिर

जिस राष्ट्र मंदिर का निर्माण इतने दिनों से अनेक आत्म-विजयी ऋषि-मुनि, दिग्विजयी सम्राट, कवि, कलाकार, साहित्यकार, स्मृतिकार, पुराणों के रचयिता तथा धर्मशास्त्रों के प्रणेता करते चले आ रहे हैं आज उस मंदिर में राष्ट्र-पुरुष की मूर्ति स्थापित करके उसे आमंत्रित करना है। भगवान को धन्यवाद दें कि वह सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। हम इस मंदिर के प्रथम पुजारी बनें। ऐसा प्रबंध कर चलें कि पीछे आने वाली पीढ़ियां इस मंदिर मं अनंत काल तक पूजा कर सकें।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

जम्मू-कश्मीर की समृद्धि के लिए आपसी विश्वास आवश्यक

जम्मू एवं कश्मीर ने एक नया इतिहास रचा है। भाजपा और पीडीपी प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए साथ आये हैं। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब प्रदेश की जनता एक नये भविष्य की ओर देख रही थी तथा पूरा देश एक नई आशा एवं उत्साह से भर रहा था। यह भारतीय राजनीति में एक नये दौर के सवेरा की तरह था। जब इस सरकार को एक ऐसे पहल के रूप में देखा जा रहा है जिसमें आपसी सौहार्द एवं विश्वास के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारें मिलजुलकर लम्बे समय से उलझी समस्याओं का चिरस्थाई हल ढूंढ पायेंगी। यह जम्मू एवं कश्मीर की जनता की सच्ची विजय है जिन्होंने विधानसभा चुनावों में पूरे उत्साह एवं जोश-खरोश से प्रदेश की उन्नति एवं खुशहाली के लिए मतदान किया है।

जम्मू एवं कश्मीर की जनता को दो महीने तक प्रदेश में अपनी सरकार को देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। विधानसभा चुनाव जिसके नतीजे 23 दिसंबर को घोषित हुए थे, ने एक खंडित जनादेश दिया जिसमें पीडीपी को 28 तथा भाजपा को 25 सीटें मिलीं।

नेशनल कांफ्रेंस एवं कांग्रेस को 87 सदस्यीय विधानसभा में क्रमश: 15 और 12 सीटें प्राप्त हुईं। पीडीपी एवं भाजपा में दो महीने तक सरकार बनाने के संबंध में बातचीत चलती रही और अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर आपसी समझ बनने के बाद 1 मार्च 2015 को सरकार बनी। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री तथा भाजपा के निर्मल सिंह ने उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। राज्यपाल एन.एन. वोहरा के द्वारा 25 मंत्रियों जिसमें पीडीपी के सईद सहित 13 और भाजपा-पीपुल्स कांफ्रेंस के 12 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया। पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन भाजपा कोटे से मंत्री बने। सरकार ने प्रदेश की जनता के विकास एवं प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दुहराया है।

पीडीपी-भाजपा सरकार, जो कई राजनीतिक विश्लेषकों को असंभव सा लगता था, दोनों तरफ की कड़ी मेहनत से तब वास्तविकता में बदल गई जब वे अपने ''न्यूनतम साझा कार्यक्रम'' बनाने में सफल हो गये। 16 पृष्ठ के 'गठबंधन के कार्यक्रम' के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सहमति बनाते हुए भविष्य की कार्यनीति तैयार की गई। जबकि धारा 370 पर यथास्थिति बनाये रखने की बात की गई। एएफएसपीए का परीक्षण कर अशांत क्षेत्र को चिन्हित करने की बात की गई है। सरकार से यह भी अपेक्षित है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाकर उनकी रोजी-रोटी को चिंता करेगी। पीडीपी-भाजपा के बीच सहमति के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा पहली बार सरकार में आई है। यह भाजपा के लिए एक भावनात्मक क्षण है क्योंकि शुरू से ही जम्मू-कश्मीर भाजपा के हृदय से जुड़ा विषय रहा है। जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का बलिदान जम्मू-कश्मीर के प्रश्न को उठाने के क्रम में ही हुआ था। इससे पूर्व भाजपा कभी भी प्रदेश में इतनी सीटें नहीं जीत पाई थी। जम्मू में भारी समर्थन के फलस्वरूप भाजपा ने 25 सीटें जीती तथा दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यह पीडीपी से मात्र तीन सीटें पीछे रही। ऐसा पहली बार हुआ कि कश्मीर घाटी में भी भाजपा ने अपनी उपस्थिति का अहसास कराया। इसके सभी प्रत्याशियों ने बहुत गंभीरता एवं मजबूती से चुनाव लड़ा। लेकिन घाटी में पीडीपी को भारी समर्थन मिला, जिसके फलस्वरूप वह 28 सीटें जीत पाई। इसलिए यह स्वाभाविक था कि पीडीपी-भाजपा सरकार जम्मू एवं कश्मीर दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती। इसलिए पीडीपी-भाजपा सरकार प्रदेश की दोनों बड़े क्षेत्रों की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के लिए कार्य करेगी। यह भाजपा के लिए एक अवसर भी है कि वहां कड़ी मेहनत कर कश्मीर घाटी की जनता के बीच भी अपना स्थान बनाये। जम्मू-कश्मीर तभी विकास कर सकता है जब दोनों बड़े क्षेत्र प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए एक-दूसरे के करीब आयें। यह सही समय है कि एक विकसित प्रदेश के लिए आपसी सौहार्द एवं विश्वास का निर्माण हो ताकि एक सुदृढ़ वैभवशाली भारत का सपना पूरा हो सके। ■

जम्मू-कश्मीर में पहली बार भाजपा सरकार में

संवाददाता द्वारा

जम्मू-कश्मीर में 1 मार्च को पहली बार भाजपा-पीडीपी की सरकार बनी। इतिहास में पहली बार भाजपा यहां किसी सरकार का हिस्सा बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में राज्य के 12वें मुख्यमंत्री

के रूप में शपथ ली। राज्यपाल श्री एन एन वोहरा ने जम्मू में 79 वर्षीय श्री सईद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 24 मंत्रियों ने भी शपथ ली।

शपथग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती सईद ने कहा कि राज्य के सभी लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए हम इस गठबंधन को इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनाना चाहते हैं।

पीडीपी-भाजपा गठबंधन के एजेंडे में कहा गया कि श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार अफस्पा के संदर्भ में अशांत इलाकों को गैरअधिसूचित करने की जरूरत पर गौर करेगी। गठबंधन के एजेंडे में कहा गया कि पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की आजीविका के लिए कदम उठाएगी। सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से 1947, 1965 और 1971 के दौरान आए शरणार्थियों का एक बार में पुनर्वास करने को लेकर काम करेगी। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भाजपा और पीडीपी ने धारा 370 को लेकर यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई, कहा कि 'विशेष दर्जे सहित सभी संवैधानिक प्रावधानों पर वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी।'

जम्मू कश्मीर में पीडीपी के वरिष्ठ नेता श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने एवं नई सरकार के काबिज होने के साथ ही 49 दिन के राज्यपाल शासन का समापन हुआ। गत 24 फरवरी को सरकार गठन को लेकर दिल्ली में पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह से उनके आवास पर भेंट की थी।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, राष्ट्रीय महासचिव श्री रामलाल एवं श्री राम माधव भी उपस्थित रहे।

सईद के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता श्री निर्मल सिंह को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। श्री सिंह पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। श्री सज्जाद गनी लोन ने भाजपा कोटे से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर सईद के शपथ ग्रहण के साथ राज्य में उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे के बाद लगे राज्यपाल शासन के 49 दिन का अंत हो गया।

गौरतलब है कि बीते 23 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 28 विधायकों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी और 25 विधायकों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। नेशनल कांफ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो आज इतना सशक्त दिख रहा है और इसे राज्य में पहली बार सरकार में आने का जो अवसर मिला है, इस गौरवशाली स्थिति के लिए अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने 'एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान-नहीं चलेंगे' इस नारे की खातिर अपना बलिदान दिया था। जम्मू-कश्मीर के प्रति भाजपा का प्रारंभ से एक विशिष्ट राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रहा है। राज्य में भाजपा समर्थित सरकार होने से जहां अलगाववाद व आतंकवाद खत्म होगा, वहीं अब यह विकास की मुख्यधारा में भी शामिल होगा। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : सदस्यता अभियान

भाजपा ने 31 मार्च तक लक्ष्य-प्राप्ति का संकल्प किया : अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 5 मार्च 2015 को तमिलनाडु के कोयम्बेटूर नगर पहुंचे और उन्होंने भाजपा के राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ राज्य में पार्टी को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। पार्टी के राज्य एवं जिला पदाधिकारियों के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, चुनावी भ्रष्टाचार के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है और यह आवश्यक है कि भाजपा को इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत बनकर तमिलनाडु में बदलाव लाना होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भाजपा को बूथ स्तर पर मजबूत करना होगा ताकि मतदाता चुनाव में धनबल के दुरुपयोग सम्बन्धी मामलों में सतर्क रहे और इसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा और चुनाव के दौरान इसे रोकना होगा।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु देश का ऐसा राज्य है जहां चुनाव के दौरान पैसे की बड़ी भूमिका नजर आती है। इसे रोकने के लिए भाजपा को बूथ और जमीनी स्तर पर दृढ़ करना होगा ताकि मतदाता को सतर्क किया जा सके और वे धनबल के सामने न झुकें।

श्री अमित शाह ने आगे कहा कि भाजपा का राज्य में 60 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इस समय 60 लाख के लक्ष्य में से 23 लाख सदस्य बन चुके हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि इस वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदस्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वयं को पार्टी के साथ और अधिक आंतरिक मेलजोल बढ़ाना चाहिए, कार्यकर्ता आधार बढ़ा कर लोगों तक पहुंचना चाहिए तथा उन्हें केन्द्र में एनडीए नीत भाजपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह भी कहना कि हमने प्रत्येक कार्यकर्ता को एक पुस्तिका दी है जिसमें नए, सक्रिय सदस्यों को एनरोल करने के लिए 100 फार्म लगे हैं। तमिलनाडु में, अभी तक 22 लाख नए सदस्य बनाए जा चुके हैं जिसमें से 8-9 लाख सदस्य स्वयं ही पार्टी में शामिल हुए हैं। तमिलनाडु में सदस्यता अभियान के लिए जारी 53,000 पुस्तकों का प्रयोग हो चुका है और सदस्य बनाए गए हैं। कार्यकर्ताओं के अभी और 25 दिन शेष हैं जिसमें वे लगभग 40 लाख और सदस्य बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में 60 लाख सदस्य बनाने का हमारा अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं और कहा कि यदि हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित ही भाजपा को भारी लाभ

होगा। अभी तक हमने लगभग 23 लाख सदस्य बनाये हैं और उन्होंने ऐसे कुछ सुझाव भी दिए जिनसे इस वांछित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।

श्री शाह ने आगे कहा कि लगभग 6.36 करोड़ नए सदस्य बनाए जा चुके हैं और आशा व्यक्त की कि 31 मार्च तक अगले 25 दिनों में पार्टी का 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

उन्होंने उल्लेख किया पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनावों में 17 करोड़ से अधिक मत प्राप्त हुए थे तो यदि प्रत्येक परिवार से तीन नए सदस्य बनाए जाएं तो यह संख्या 10 करोड़ बन सकती है जिससे हमारी सदस्य संख्या 30 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसा होने से हम अगले चुनावों में आसानी से 370 सीटों पर विजय मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि यदि हम 60 लाख सदस्य बना लें तो निश्चित ही प्रत्येक चुनावी बूथ पर हमारी प्रमुख उपस्थिति दर्ज हो जाएगी जिससे हम जमीनी स्तर से चुनावी दुराचार दूर कर सकेंगे और कार्यकर्ता राज्य में भाजपा के विकास के लिए अधिक परिश्रम करें।

उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का गहरा महत्व है और कहा कि इसके अभाव में हमने देखा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी संसद में मात्र 44 सदस्यों तक सीमित रह गई क्योंकि उसने सदस्यता अभियान पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा यह गलती नहीं करेगी और हम सदस्यता अभियान के प्रति समर्पित रहेंगे।

भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान का लक्ष्य विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनना है जिसमें भाजपा के मार्च के अंत तक दस करोड़ सदस्य बनाना है जिससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आठ करोड़ सदस्यों ने लक्ष्य को मात दी जा सके।

श्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में 2014 के संसदीय चुनावों में भाजपा गठबंधन को 19 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। यदि पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता तो हमें और भी अधिक मत प्राप्त हो सकते थे।

भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान का लक्ष्य विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनना है जिसमें भाजपा के मार्च के अंत तक दस करोड़ सदस्य बनाना है जिससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आठ करोड़ सदस्यों ने लक्ष्य को मात दी जा सके। अभी तक पार्टी 6.36 करोड़ बना चुकी है। मुझे विश्वास है कि भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान सह-संयोजक निश्चित ही इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। संभव है कि हम 15 दिन या एक महीने तक इस अभियान का विस्तार कर दें।

डा. सहस्रबुद्धे ने कहा कि भाजपा की योजना में तमिलनाडु का गहरा महत्व है और भाजपा यहां पर अपनी उपस्थिति स्वयं ही दर्ज कराना चाहती है।

यह उल्लेखनीय है कि पार्टी ने एक नए विजन, संकल्प और 'सशक्त भाजपा, सशक्त भारत' नारे के साथ जोरदार शुरुआत की है। अत: पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 नवम्बर 2014 को राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर पार्टी के लिए प्राइमरी सदस्यों की संख्या को तीन से चार गुना बढ़ाने का संकल्प किया। अभी तक सदस्यता अभियान शुरू करने के दिन से लगभग 6.36 करोड़ ऑन-लाइन सदस्यों ने प्राइमरी सदस्यों के रूप में सदस्यता ग्रहण कर ली है।

भाजपा के लिए सदस्यता अभियान कोई नई बात नहीं है। हर बार, संगठन के समारोह के रूप में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होता है और प्रत्येक सदस्य को हर छ: वर्ष के बाद सदस्य बनना होता है। यह भाजपा की परम्परा रही है। लगभग 1300 पार्टियों में से केवल एक या दो पार्टियों में ही आंतरिक लोकतंत्र व्याप्त है और इसमें लोगों को व्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। पार्टी के साथ जुड़ने के बाद

सदस्य संगठन से जुड़ता है और ऐसी व्यवस्था बनी है जिससे इस व्यवस्था से जुड़कर चुनाव के माध्यम से किसी भी पद तक पहुंच सकता है। कोई भी सदस्य आगे आकर इस मंच से देश की सेवा में लग सकता है। इस सभ्य देश में एकमात्र भाजपा ही ऐसी राजनैतिक पार्टी है जो हर छ: वर्ष के अन्तराल पर इस प्रकार सदस्यता अभियान चलाती है। वर्तमान अभियान 31 मार्च 2015 तक चलेगा।

पहले की तरह भाजपा भारी पैमाने पर सदस्यता अभियान चला रही है परन्तु जहां तक मैकेनिज्म का सम्बंध है, पारम्परिक तरीकों के अलावा पहली बार पार्टी टैक्नालाजी का इस्तेमाल कर रही है और मोबाइल फोन पर सदस्य बना रही है। कोई भी व्यक्ति, जो सदस्य बनना चाहता, वह पार्टी का प्राइमरी सदस्य बनने के लिए 18002662020 पर फोन कर सकता है। परन्तु जिन व्यक्तियों के पास मोबाइल फोन नहीं है, उन्हें 9242492424 पर एसएमएस भेजना होगा और वह भाजपा का सदस्य बन सकता/सकती है।

सक्रिय सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 100 प्राइमरी सदस्य बनाना अनिवार्य है। इस बार भाजपा ने सक्रिय सदस्यों में 50 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया है जो पहले 5.5 से 6.0 लाख था। यदि किसी राज्य में 100 सक्रिय सदस्य हैं तो उसे 50 प्रतिशत अधिक सदस्य बना कर 150 सदस्य बनाने होंगे। यदि पूरे देश में 6 लाख सक्रिय सदस्य है तो हम इस बार 9 लाख सक्रिय सदस्य बनाना चाहते हैं। पार्टी ने सक्रिय सदस्य बनने के सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन किए हैं। जो व्यक्ति सक्रिय सदस्य बनना चाहता है तो उसे ऐसे किसी इलाके, मलिन बस्ती, दलित बस्ती, गांव या ब्लॉक में 7 दिन का समय देना होगा, जहां भाजपा का कोई सदस्य नहीं है और उसे सदस्य बनाने का काम करना होगा और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसके बाद उसके काम को प्रमाणित किया जाएगा तो उसे सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक सक्रिय सदस्य को 100 सदस्य बनाने होंगे। यदि 9 लाख सक्रिय सदस्य में से प्रत्येक 100 सदस्य बनाता है तो 9 करोड़ सदस्य आसानी से बन जाते हैं। और जो केवल 100 सदस्य बनाते है तो उन्हें 100 सदस्यों की सूची देनी होगी।

इस बारे में एक पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें उस सक्रिय सदस्य का नाम, मंडल, जिला, राज्य, मोबाइल नम्बर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वह सदस्य जो कौंसिलर बनने जा रहा है, तो उसके सामने डायल करने के लिए टोल फ्री नम्बर रहेगा। एक परिवार में एक से अधिक सदस्य बनाए जा सकते हैं। भाजपा का संकल्प है कि यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर बूथ-स्तर के कार्यकर्ताओं में सख्ती से अपनाई जाएगी।

31 मार्च के बाद संगठन ने वर्ष 2015 के पूरे वर्ष को 'सदस्यता पर्व वर्ष' मनाने का निर्णय लिया है। जिससे इस देश के प्रत्येक घर तक पहुंचा जा सके अर्थात् 'घर-घर

शेष पृष्ठ 22 पर

7 मार्च 2015 तक बने सदस्य

क्र.	सर्किल	7 मार्च तक
1	उत्तर प्रदेश(पूर्व)	77,84,073
2	गुजरात	67,36,157
3	मध्यप्रदेश-छत्तिसगढ़	65,80,594
4	कर्नाटक	52,14,136
5	महाराष्ट्र-गोवा	47,79,647
6	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)-उत्तराखंड	47,79,014
7	राजस्थान	39,33,617
8	बिहार-झारखंड	37,35,281
9	दिल्ली	29,30,322
10	नॉट एलोकेटिड	18,70,956
11	असम	17,82,254
12	हरियाणा	17,20,500
13	ओड़िशा	16,98,828
14	प. बंगाल-अंडमान निकोबार	15,38,082
15	मुम्बई	15,36,980
16	तमिलनाडु	14,90,755
17	आंध्र प्रदेश	12,85,132
18	पंजाब	12,71,875
19	केरल	11,64,904
20	कोलकाता	6,64,506
21	चेन्नई	4,01,905
22	जम्मू-कश्मीर	3,30,572
23	उत्तर-पूर्व	2,05,466
24	हिमाचल प्रदेश	1,89,414
25	तमिलनाडु-चेन्नई	6,255
	योग	**6,36,28,225**

आर्थिक सर्वेक्षण से बंधी उम्मीदें

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद में 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 प्रस्तुत किया। इस समीक्षा में अगले वित्त वर्ष में 8.1 से 8.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाते लगाते हुए आगे बड़े आर्थिक सुधारों को आगे बढाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2014-15 की समीक्षा में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में दहाई अंक की उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए कारोबारी माहौल सुधारने और कर दरों को नरम रखने की जरूरत है।

मुख्य बातें

- बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधारक कदम उठाए गए।
- राष्ट्रीय सौर मिशन का आकार पांच गुणा बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट किया गया।
- स्वच्छ ऊर्जा उपकरण दोगुणा कर प्रति टन 100 रुपये कर दिया गया। इससे 17,000 करोड़ रुपये की आय होगी।
- तेज विकास के लिए कार्योन्मुख नीतियां, जबकि जलवायु परिवर्तन से लक्षित तरीके से निपटा जा रहा है।
- सेवा क्षेत्र में दहाई अंकों में विकास दर 10.6 फीसदी।
- बाहरी क्षेत्र में मजबूती की वापसी।
- भारतीय रेल की संरचना, वाणिज्यिक पद्धति और प्रौद्योगिकी में सुधार करने की सिफारिश।
- विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे में अधिक सरकारी निवेश।
- 2011-12 के बाद से आठ प्रमुख उद्योगों की विकास दर औद्योगिक विकास दर से अधिक।
- औद्योगिक विकास बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए गए।
- सरकार वित्तीय घाटा कम करने के लिए प्रतिबद्ध, राजस्व बढ़ाना एक प्राथमिकता।
- देश को अतिरिक्त वित्तीय स्थान बनाने की जरूरत।
- पुरुष साक्षरता 80.9 फीसदी, महिला साक्षरता 64.6 फीसदी।
- मेक इन इंडिया और स्किलिंग इंडिया के बीच संतुलन की जरूरत, कौशल विकास और रोजगार प्रमुख चुनौतियां।
- 2014-15 में (जनवरी तक) खाद्य सब्सिडी खर्च 1,07,823.75 करोड़ रुपये, एक साल पहले के मुकाबले 20 फीसदी अधिक।
- सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने से कृषि में सरकारी निवेश के लिए संसाधन तैयार होंगे।
- कृषि उत्पाद के लिए राष्ट्रीय साझा बाजार तैयार होंगे।
- निवेश का माहौल बेहतर करने के लिए सरकारी निवेश में फिर से तेजी लानी होगी।
- अप्रैल-दिसंबर 2014-15 में महंगाई में गिरावट का रुझान, औसत डब्ल्यूपीआई महंगाई दर घटकर 3.4 फीसदी, जो एक साल पहले समान अवधि में औसत छह फीसदी थी, डब्ल्यूपीआई खाद्य महंगाई दर घटकर 4.8 फीसदी, जो एक साल पहले समान अवधि में 9.4 फीसदी थी, सीपीआई महंगाई दर 5 फीसदी के रिकार्ड निचले स्तर पर, जो गत दो साल में 9-10 फीसदी थी।
- खाद्य महंगाई कम करने की सरकारी कोशिश और कच्चे तेल के मूल्य में लगातार गिरावट के कारण महंगाई दर में गिरावट।
- अनाज उत्पादन 2014-15 में 25.707 करोड़ टन अनुमानित। यह गत पांच साल के औसत अनाज उत्पादन से 85 लाख टन अधिक रहेगा।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीडीपी में 18 फीसदी योगदान करेंगे।
- 14वें वित्त आयोग से वित्तीय संघवाद को मिलेगा बढ़ावा।
- प्रौद्योगिकी स्टार्टअप क्षेत्र में काफी तेज विकास।
- गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की पहुंच से 'मेक इन इंडिया मिशन' को मिलेगा बल।
- इलेक्ट्रॉनिक वीसा से पर्यटन क्षेत्र में आएगी तेजी।
- 2015-16 में आठ फीसदी से अधिक विकास दर अनुमानित।
- दहाई अंकों में विकास दर अब संभव।
- जनादेश सुधार के लिए और बाहरी माहौल जोखिम रहित।
- व्यापक सुधार की गुंजाइश। ■

अब तीव्र विकास का दौर : अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 पर दिप्पणी करते हुए कहा कि राजग सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति में आए सुधार का प्रमाण है। आर्थिक समीक्षा दर्शाती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार सबका साथ, सबका विकास की राह पर चलकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना शीघ्र साकार होगा।

- आर्थिक समीक्षा का अनुमान वित्त वर्ष 2015-16 में विकास दर 8.1-8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
- आने वाले वर्षो में 8-10 प्रतिशत रहेगी विकास दर, दहाई अंक (डबल डिजिट) में विकास दर संभव
- 74193 रुपये हुई प्रति व्यक्ति आय
- थोकमूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जीरो प्रतिशत पर आई
- राजग सरकार का ध्येय ''हर आंख से आंसू पोंछना'' है। इसके लिए जैम नं. (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) के त्रिसूत्रीय समाधान का सहारा लिया जाएगा
- सब्सिडी को तर्कसंगत बनाकर और लाभार्थियों तक पहुंचाएगी सरकार
- खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 25.70 करोड़ टन रहने का अनुमान, पिछले पांच साल के औसत के मुकाबले 85 लाख टन अधिक होगा खाद्यान्न उत्पादन
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीडीपी में 18 फीसदी योगदान
- कृषि उत्पाद के लिए राष्ट्रीय साझा बाजार तैयार होंगे
- गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की पहुंच से मेक इन इंडिया मिशन को मिलेगा बल
- युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' पर जोर
- औद्योगिक विकास दर में भी तेजी आई है
- एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में राजग सरकार ने उठाए कई कदम
- राजकोषीय संतुलन के लिए प्रतिबद्धता, राजस्व बढाने के प्रयास पर जोर
- देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी हुई बढ़ोतरी
- चालू खाते का घाटा 2015-16 के दौरान घटकर करीब 1 प्रतिशत पर आ जाएगा
- राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य कायम
- वित्त वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य
- बड़े सुधारों की तैयारी, जीएसटी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) निभाएंगें की अहम भूमिका
- संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की स्थापना
- चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने संबंधी सिफारिश को सरकार ने स्वीकार किया
- निर्यात बढ़ा और विदेशी पूंजी के आगम में भी मजबूती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा अब तक किए गए प्रयासों से अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई और विकास दर में तेजी आई है। संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2014-15 इस बात की पुष्टि करती है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि कि वित्त वर्ष 2015-16 में विकास दर 8.1 से 8.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में देश की प्रति व्यक्ति आय 74193 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी, लगातार महंगाई, बढ़ते

राजकोषीय घाटे, घटती घरेलू मांग और बाह्य खाता असंतुलनों और रुपए की घटती कीमतों के दौर को पीछे छोड़कर तेजी से उच्च विकास दर की ओर अग्रसर हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच उज्ज्वल है और माना जा रहा है कि देश जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दहाई के अंक में पहुंच जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार की नीति- सबका साथ, सबका विकास है। इसलिए जब देश उच्च विकास दर के साथ आगे बढ़ेगा तो उससे वंचितों और गरीब लोगों की हर आंख से आंसू पोंछने का मौलिक उद्देश्य प्राप्त होगा। यह युवा, मध्यम वर्ग और आकांक्षा रखने वाले भारत को अपनी पूरी क्षमता का अहसास कराने का अवसर भी प्रदान करेगा।

दरअसल राजग सरकार ने अपने 9 महीने में ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को सुविधाएं देने, युवाओं को रोजगार मुहैया कराने, महिलाओं को सुरक्षा देने, बच्चियों की शिक्षा और लालन-पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसे कार्यक्रम भी शुरु किए हैं जिससे देश का औद्योगिक विकास होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने देश में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा कई और सुधारों को सरकार लागू करने की प्रक्रिया में है। इससे भारत आज दुनिया भर के निवेशकों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार द्वारा तेजी से उठाए निर्णायक कदमों से, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में, व्यापक कमी आई है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति नवंबर 2014 और जनवरी 2015 में 0 प्रतिशत के मनौवैज्ञानिक स्तर को भी छू गयी थी। सरकार ने खाद्यान्नों में उपलब्धता सुधारने और वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए अनेक कदम उठाए। सभी राज्यों में गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से ऊपर (बीपीएल और एपीएल) रहने वाले परिवारों के लिए 50 लाख टन अतिरिक्त चावल का आवंटन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लंबित कार्यान्वयन और 2014-15 में घरेलू बाजार के लिए खुले बाजार में बिक्री करने के अधीन 10 मिलियन टन गेहूं का आवंटन।

कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम से फलों और सब्जियों को गैर-सूचीबद्ध करके उनकी मुक्त ढुलाई करने की अनुमति देने के लिए राज्यों को सलाह दी। प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन लाना जिससे जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति प्रदान करना तथा स्टॉक सीमा का उल्लंघन को गैर-जमानती बनाया। 26 जून 2014 से आलू का न्यूनतम निर्यात मूल्य 450 अमरीकी डॉलर तथा प्याज का 300 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन लागू किया।

आर्थिक समीक्षा में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि राजग सरकार ने किसानों के लिए पिछले और चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोत्तरी। आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय साझा कृषि बाजार की जरूरत पर जोर दिया गया। वर्तमान में एपीएमसी जो विविध शुल्क वसूल करती है उनमें पारदर्शिता नहीं है। विक्रेता और किसानों के बीच लेनदेन में कमीशन एजेंट, भारी कमीशन शुल्क वसूलते हैं। वैट और मंदी टैक्स हर राज्य में अलग-अलग हैं जो मूल्यों को बढ़ाने में प्रभाव डालते हैं। एपीएमसी एक्ट में सुधार से किसानों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हैं। यही वजह है कि राजग सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं जिनमें नदियों का संरक्षण, शहरी वायु की गुणवत्ता में बेहतरी, वनीकरण में वृद्धि, नवीकरणीय उर्जा के स्रोतों में वृद्धि, लोक यातायात के साधनों में वृद्धि, तथा शहरी तथा ग्रामीण अवसंरचना का विकास शामिल है।

इस बारे में हालिया महत्वपूर्ण पहल स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा योजना, राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन को पांच गुना बढ़ाकर 20000 मेगावाट से 100000 मेगावाट करना शामिल है। इस बात को भी आर्थिक समीक्षा में रेखांकित किया गया है।

इस तरह आर्थिक समीक्षा 2014-15 राजग सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति में आए सुधार का प्रमाण है। आर्थिक समीक्षा दर्शाती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार सबका साथ, सबका विकास की राह पर चलकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना शीघ्र साकार होगा। ■

सरकार की उपलब्धियां : चौदहवां वित्त आयोग

‘ एनडीए सरकार ने देश के समग्र विकास के लिए कदम उठाए हैं ’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह की ओर से जारी बयान आयोग की सिफारिशें पूर्णत: स्वीकार करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार को बहुत-बहुत बधाई। राजग सरकार के इस कदम से राज्यों को विशेष लाभ होगा। राज्यों को पहला फायदा केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने के रूप में होगा। अब तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी मात्र 32 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगी। इस तरह इसमें 10 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि होगी। इससे पहले किसी भी वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में इतनी वृद्धि नहीं की। इससे केंद्र के वित्तीय संसाधनों पर दवाब पड़ेगा लेकिन राजग सरकार ने अपनी सहकारी संघवाद की नीति पर चलकर राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की खातिर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें सहर्ष स्वीकार की हैं जो निश्चित तौर पर सराहनीय है। अब राज्यों को केंद्र से अधिक धनराशि प्राप्त होगी जिसे वे अपनी जरूरत के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता बढ़ेगी।

केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की उस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है जिसके तहत पंचायतों और नगर निकायों को 2.87 लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की गई है। इससे गांव और शहरों में स्थानीय निकायों को लोगों की जरूरत के हिसाब से विकास कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर कदम उठाकर गरीबों की कल्याण और देश के समग्र विकास के लिए कदम उठाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजग सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार करना है जिसमें उसने राजस्व घाटे का सामना कर रहे 11 राज्यों को भारी भरकम 1.94 लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को साथ लेकर चलने के के लिए टीम इंडिया की अवधारणा पर जोर दिया है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजग सरकार ने नीति आयोग की स्थापना भी की है जिसमें नीति निर्माण में केंद्र और राज्यों की बराबर भूमिका है। वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाकर देश के संघीय संरचना को मजबूती देने का काम किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर कदम उठाकर गरीबों की कल्याण और देश के समग्र विकास के लिए कदम उठाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजग सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार करना है जिसमें उसने राजस्व घाटे का सामना कर रहे 11 राज्यों को भारी भरकम 1.94 लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की है। इनमें से अधिकांश राज्य गैर-भाजपा शासित राज्य हैं। इस तरह किसी भी राज्य में भले ही किसी भी दल की सरकार हो, राजग सरकार का मकसद देश का संपूर्ण विकास है। इसके अलावा राजग सरकार ने हाल में कई और भी ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गरीब और पिछड़े राज्यों को फायदा हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता की नीति को अमल में लाकर कोयला खदानों की नीलामी की है। इससे खनिज और कोयला समृद्ध राज्यों को लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति होगी। इसका लाभ पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों को लाभ होगा। ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी हैं लेकिन पूर्व की सरकारों की भेदभाव वाली नीतियों के कारण आर्थिक विकास के मामले में पिछड़ गए हैं। राजग सरकार की इस कदम से इन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकेंगे जिससे इन राज्यों को विकास की राह में बराबरी पर आने का अवसर प्राप्त होगा। इस तरह सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलकर राजग सरकार एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। ■

हमारी राष्ट्रीयता

✍ पंडित दीनदयाल उपाध्याय

भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार्यता की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। औपनिवेशिक शासन ने न केवल भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के सामने चुनौतियां प्रस्तुत कीं, बल्कि भारत की सामूहिक एकता के संदर्भ में बौद्धिक संकट भी खड़े किए। दुर्भाग्य से बहुत से भारतीय 'राष्ट्र' की पश्चिमी अवधारणा के प्रभाव में आकर इसके विकृति अर्थों से बच न सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संदर्भ में इसकी बौद्धिक व सांस्कृतिक परिभाषा दी। 'हमारी राष्ट्रीयता' शीर्षक से प्रकाशित उनके विचारों को हम दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं ताकि 'राष्ट्र' की अवधारणा स्पष्ट हो सके। हमारे सुधी पाठकों के लिए इसका प्रथम भाग निम्न है:

राष्ट्र क्या है?

जब लोगों का समूह एक लक्ष्य, एक आदर्श, एक ध्येय के लिए किसी विशेष क्षेत्र को मातृभूमि समझते हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि आदर्श या मातृभूमि दोनों में कोई एक नहीं है तो कोई राष्ट्र नहीं हो सकता।

राष्ट्र के अवयव

एक राष्ट्र को 4 अवयवों की जरूरत होती है। प्रथम भूमि या लोग जिसे हम देश कहते हैं। दूसरी समाज की सामूहिक इच्छा। तीसरी एक व्यवस्था जिसे हम संविधान कह सकते हैं, जिसे और भी उपयुक्त रूप से 'धर्म' कह सकते हैं। और चौथा जीवन आदर्श है। इन सभी का समेकित रूप राष्ट्र है। एक व्यक्ति का निर्माण शरीर, मन व बुद्धि से होता है, वहीं राष्ट्र का निर्माण भूमि, सामूहिक इच्छा, धर्म और आदर्श से होता है।

राष्ट्र स्थायी है

राष्ट्र एक स्थायी सत्य है। राज्य का निर्माण राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। राज्य की उत्पत्ति के पीछे दो कारण बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दो परिस्थितियों में राज्य अपरिहार्य है। पहला यह कि जब राष्ट्र के लोगों में विकृति प्रवेश करती है। राज्य का निर्माण इन समस्याओं से निपटने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई झगड़ा नहीं है तो पुलिस की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि कोई विवाद है तो पुलिस को तत्काल बुलाया जाता है। दूसरा जब समाज में कोई जटिलता आती है तो इसे व्यवस्था में लाने के लिए राज्य की जरूरत पड़ती है।

राज्य का निर्माण इसलिए किया जाता है कि शक्तिशाली, समृद्ध और संसाधनों से परिपूर्ण वर्ग गरीब, बेसहारा व कमजोर लोगों का शोषण न कर सके और सभी लोगों को न्याय मिल सके। इन्हीं दो कारणों से राज्य का निर्माण किया जाता है। समाज में आई विकृति को ठीक करने के लिए, गलत लोगों

को दंड देकर शांति स्थापित करने में तथा समाज की जटिलता को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है ताकि सभी न्याय व सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तीसरे महत्वपूर्ण कार्य की जरूरत होती है। वह है दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करना। इसलिए सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से बचाव भी राज्य के कार्य हैं।

राष्ट्र का व्यक्तित्व

भारत शब्द राष्ट्र को उद्बोधित करता है, जबकि उत्तर-प्रदेश व बंगाल प्रांत जैसे नाम इसे उद्बोधित नहीं करते। इसलिए यह बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि निश्चित भू-भाग राष्ट्र के लिए प्रथम आवश्यक शर्त है, लेकिन सिर्फ क्षेत्र राष्ट्र नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र का अस्तित्व उन अवयवों पर निर्भर करता है, जो अदृश्य तो हैं, लेकिन उनकी प्रबल अनुभूति होती है। राष्ट्र का भी व्यक्तित्व होता है, जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। जब यह कमजोर होता है तो राष्ट्र कमजोर होता है। जब इसे भुला दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है तो राष्ट्र का स्वरूप भी छिन्न-भिन्न हो जाता है। यही वजह है कि पिछले काल के कई राष्ट्र सिर्फ यादों में रह गए हैं। उनके क्षेत्र और उन पर रहने वाले लोग आज भी हैं, लेकिन प्राचीन काल के यूनान, ईरान और मिस्र मिट गए हैं। दूसरे शब्दों में उनका राष्ट्रीय व्यक्तित्व खो गया है। यह व्यक्तित्व ही है, जिस पर राष्ट्र टिका होता है।

राष्ट्र संरचना

राष्ट्र का निर्माण किसी स्वार्थपरक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होता। मानव शरीर के विभिन्न अंगों के अपने स्वाभाविक कार्य हैं, इन्हें प्रेरित या उकसाना नहीं पड़ता है। उसी तरह से राष्ट्र के सभी तत्त्व एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं और इसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय भावना के बिखराव से राष्ट्र के अंग कमजोर होते हैं। यदि ये पूर्णत: निष्क्रिय हो जाते हैं तो उसका परिणाम राष्ट्र की समाप्ति से होता है। लेकिन यदि इन अंगों में राष्ट्रीय भाव प्रबल होता है तो ये पुन: अपने स्वाभाविक कार्य करने लगते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्र का आधार एक व्यावहारिक व स्वाभाविक संगठन होता है, जो स्थायी, मजबूत और आत्मनिर्भर होता है। यदि राज्य के संगठन शक्तिशाली हैं, तो इसके अंग भी उतने ही शक्तिशाली होंगे।

राष्ट्र की आत्मा

राष्ट्र के पास भी आत्मा होती है। इसका तकनीकी नाम है 'चिति'। मैकडूगल के अनुसार यह एक वर्ग की सहज प्रकृति है। प्रत्येक वर्ग की एक सहज प्रकृति होती है। इसी तरह प्रत्येक समाज की एक सहज अंतभूति प्रकृति होती है, जो ऐतिहासिक घटनाओं की परिणामस्वरूप नहीं होती।

'चिति' राष्ट्र की कसौटी है

'चिति' एक पैमाना है जिस पर सभी कार्य, व्यवहार की जांच होती है। परिणामस्वरूप इसकी स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता का निर्णय किया जाता है। 'चिति' राष्ट्र की आत्मा है। 'चिति' की शक्ति से शक्तिशाली राष्ट्र का विकास होता है। यह 'चिति' ही है जो किसी राष्ट्र के महान पुरुषों के कार्य में प्रतिध्वनित होता है।

राष्ट्र की आत्मा 'चिति' को उभारने में एक व्यक्ति भी साधन के रूप में कार्य करता है। इसलिए व्यक्ति 'स्वयं' के अलावा राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहीं नहीं वह राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित विभिन्न संस्थानों को संचालित भी करता है। इसलिए वह इनका प्रतिनिधित्व भी करता है। राष्ट्र से बड़े वर्ग जैसे- मानवता का भी वह प्रतिनिधित्व करता है। संक्षेप में एक व्यक्ति बहुआयामी होता है, लेकिन उनका अंतर्विरोध नहीं है, वे एक-दूसरे के पूरक व सहयोगी होते हैं। ऐसी व्यवस्था जो परस्पर पूरक प्रकृति पर आधारित हो, जिसमें मानवता के विभिन्न आदर्श समाहित हों और आपसी उपयोगिता व सहभागिता को बढ़ाते हों, वे मानवता की सुख व शांति लाते हैं और स्थायी विकास सुनिश्चित करते हैं।

राष्ट्र का आदर्श 'चिति' है

राज्य इसलिए निर्मित किया गया ताकि राष्ट्र का अस्तित्व सुरक्षित रहे और उन परिस्थितियों को बनाए रखे जिसके तहत राष्ट्र के आदर्श वास्तविकता में परिणित हो सकें। राष्ट्र के आदर्श चिति का निर्माण करते हैं। यह एक व्यक्ति की आत्मा के सदृश्य है। चिति को समझने के लिए कुछ प्रयास की जरूरत होती है। वे कानून जो चिति को बनाए रखने व इसके विस्तार में मदद करते हैं वे राष्ट्र के धर्म हैं। जो सर्वोच्च है। धर्म राष्ट्र की आत्मा का आधान है। यदि धर्म नष्ट होता है तो राष्ट्र विनष्ट हो जाता है। जो कोई धर्म का त्याग करता है, वह राष्ट्र को धोखा देता है।

जारी है...

(सुधाकर राजे द्वारा संपादित पुस्तक 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय : ए प्रोफाइल' से साभार)

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले...

23 मार्च 1931 का दिन महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का अमर बलिदान दिवस है। इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मातृभूमि के लिए इनका अमर प्रेम और विदेशियों से संघर्ष का अदम्य साहस अतुलनीय है। ये अमर बलिदानी न केवल देश के प्रेरणा पुंज हैं, बल्कि नौजवानों के आदर्श पुरुष भी हैं। समस्त देश इनका कृतज्ञ है।

महान क्रांतिकारी भगत सिंह

(27 सितम्बर, 1907 - 23 मार्च, 1931)

सरदार भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने केन्द्रीय असेम्बली की बैठक में बम फेंका और बम फेंककर वे भागे नहीं। क्रांतिकारी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को इनके साथियों, राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह को जब फांसी दी गई, तब उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियाँवाला बाग पहुँच गये। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रान्तिकारी किताबें पढ़ कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं? बहुत कम उम्र में भगत सिंह जुलूसों में भाग लेना प्रारम्भ किया तथा कई क्रान्तिकारी दलों के सदस्य बने। बाद में वे अपने दल के प्रमुख क्रान्तिकारियों के प्रतिनिधि भी बने। उनके दल के प्रमुख क्रान्तिकारियों में चन्द्रशेखर आजाद, भगवतीचरण व्होरा, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे।

जेल के दिनों में उनके द्वारा लिखे पत्रों व लेखों से उनके विचारों का पता लगता है। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत भारतीय जनता को और प्रेरित करेगा। इसी कारण उन्होंने सजा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से मना कर दिया।

उन्होंने अंग्रेजी सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ भारतीयों के युद्ध का युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए।

फांसी पर जाते समय वे गा रहे थे-

दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फ़त
मेरी मिट्टी से भी खुस्बू ए वतन आएगी।

सुखदेव थापर

(15 मई 1907-23 मार्च 1931)

सुखदेव थापर (या थापड़) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। इन्होंने भगत सिंह, कॉमरेड रामचन्द्र एवं भगवती चरण बोहरा के साथ लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। सांडर्स हत्या कांड में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था। जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने के विरोध में व्यापक हड़ताल में भाग लिया था।

शिवराम हरि राजगुरु

(1908-23 मार्च 1931)

शिवराम हरि राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। इन्होंने धर्मग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन किया तथा सिद्धांत कौमुदी इन्हें कंठस्थ हो गई थी। ये शिवाजी तथा उनकी छापामार शैली के प्रशंसक थे। ये हिन्दुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े। ■

बजट 2015-16

रोजगारपरक, विकासोन्मुखी बजट

राम नयन सिंह की रिपोर्ट

गत 28 फरवरी को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने राजग सरकार का पहला पूर्ण बजट 2015-16 पेश किया। यह बजट विकासोन्मुखी, किसानोन्मुखी व रोजगारपरक बजट है। इस बजट में गरीब वर्गों, किसानों, नौजवानों, ग्रामीण एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। गरीब वर्गों के सामाजिक सुरक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की गई है। 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के तहत जनधन योजना के अकाउंट से हर महीने एक रुपये कटेंगे। यानी मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपये के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी।

गरीबों के लिए 'अटल पेंशन योजना' शुरू की जाएगी, जिसके तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम सरकार देगी और 60 साल से अधिक आयु होने पर एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। सरकार इस पेंशन योजना में भागीदारी करने वाले अंशधारकों की तरफ से वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत या फिर 1,000 रुपये का योगदान करेगी। इनमें जो भी कम होगा वह राशि सरकार देगी। सरकार की तरफ से यह योगदान पांच सालों तक किया जाएगा।

'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' में दो लाख रुपये सहज मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। 18 से 50 आयु वर्ग के लिए इसका प्रीमियम 330 रुपये प्रतिवर्ष या प्रतिदिन एक रुपये से कम होगा। पीपीएफ में लगभग 3000 करोड़ रुपये और ईपीएफ ट्रस्ट में लगभग 6000 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशियां पड़ी हैं। इसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाएगा।

इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान किया गया है। इससे किसानों में काफी उत्साह है। किसानों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाने के लिए सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे देश के अन्नदाता किसान को आर्थिक तंगी से उबरने में काफी मदद मिलेगी।

छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रावधान रखा गया है।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 2015-16 का आम बजट पेश करते हुए कहा, ''कृषि ऋण हमारे मेहनती किसानों को सहारा देते हैं। ऐसे में मैंने 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि बैंक इस लक्ष्य को पार कर लेंगे। किसानों को तीन लाख रुपये तक का फसल ऋण सात प्रतिशत ब्याज पर मिलता है। हालांकि, यदि किसान ऋण का भुगतान समय पर करता है, तो प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत रहती है। चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 8 लाख करोड़ रुपये है। सितंबर तक 3.7 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया गया था।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को

प्रभावी व अड़चनरहित कृषि ऋण के जरिये कृषि क्षेत्र को समर्थन को मैं 2015-16 में ग्रामीण संरचना विकास कोष में 25,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने दीर्घावधि के ग्रामीण ऋण कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। इसके अलावा सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त कोष के लिए 45,000 करोड़ रुपये व लघु अवधि के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्त कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं कृषि मंत्रालय की जैव कृषि योजना 'परंपरा कृषि विकास योजना' तथा प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (एमजीएसवाई) को समर्थन का प्रस्ताव करता हूं। मैं सूक्ष्म सिंचाई जल संभरण कार्यक्रमों व पीएमजीएसवाई के लिए 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई का उद्देश्य प्रत्येक किसान के खेत की सिंचाई व पानी के इस्तेमाल की दक्षता में सुधार करना है। इसके अलावा टिकाउ आधार पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी मृदा हेल्थ कार्ड जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का लक्ष्य सभी खेतों लिए सिंचाई उपलब्ध कराना और 'प्रति बूंद अधिक कृषि' से जल का सदुपयोग बढ़ाना है। इससे जल जैसे दुलर्भ संसाधनों का न केवल बेहतर उपयोग होगा, बल्कि किसानों को कृषि-लागत कम होगी तथा उनकी आय बढ़ने में मदद मिलेगी।

सच तो यह है कि किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल उपज के उचित मूल्य को लेकर है। फसल आने के समय उन्हें लागत से कम दाम पर अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए होने वाली सरकारी खरीद बहुत कम होती है। वित्त मंत्री जेटली ने किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसान अब स्थानीय व्यापारियों के जाल में नहीं हैं, लेकिन उनकी उपज को अभी तक सर्वश्रेष्ठ अनुमानित मूल्य नहीं मिलता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम राष्ट्रीय साझा बाजार स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों को दुनिया भर में आर्गेनिक (जैविक) खेती का केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में अहम घोषणा की है। देश भर में प्राकृतिक मार के चलते फसलों के खराब होने और इससे किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने इस बजट में 2589 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 हेतु फसल बीमा के लिए 2589 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए भी 3295 करोड़ रुपए बजट में अलग से रखे गए है।

नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में आर्गेनिक खेती की अपार संभावनाओं के मद्देनजर भी सरकार ने खास कदम उठाए है। आम बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए

बजट 2015-16 की मुख्य बातें

- कर राजस्व में इजाफा होगा
- वर्ष 2017 तक वित्तीय घाटा कम कर 3.9 फीसदी तक लाने का लक्ष्य
- लघु उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए
- मनरेगा के लिए 34699 करोड़ रुपए का इंतजाम
- जन-धन योजना के तहत गरीबों के लिए दो लाख रुपए का बीमा सिर्फ 12 रुपए के प्रीमियम पर
- अटल पेंशन योजना के तहत हर खाताधारक को सरकार देगी 1,000 रुपए।
- प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हर नागरिक को बीमा सुरक्षा
- बीपीएल वर्ग के बुजुर्गों के लिए विशेष बीमा योजना
- अटल नवोन्मेष मिशन, इसके तहत शिक्षाविदों को जोड़ जाएगा
- रेल, सिंचाई व सड़क के लिए टैक्स-फ्री इनफ्रास्ट्रक्चर बांड
- लघु सिंचाई योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए
- सरकार विनिवेश से पैसे जुटाएगी
- ग्रामीण कर्ज योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए
- बाल विकास योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए
- पांच नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 70 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे
- रेलवे के लिए 10 हजार करोड़ रुपए

125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम नीली क्रांति को भी इस बजट में ध्यान में रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए 411 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही डेयरी विकास अभियान के लिए 481 करोड़ रुपए और कृषि उन्नति योजना के लिए 3257 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) तंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके लिए स्वरोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। इस प्रयोजन के लिए, नीति आयोग में आरंभिक रूप में 1000 करोड़ रुपए ये निर्धारित किए गए हैं। सच तो यह है कि अगर देश में रोजगार बढ़ाने हैं, तो स्किल इंडिया और 'मेक इन इंडिया' में तालमेल की जरूरत है।

इस संदर्भ में श्री अरुण जेटली ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए भारत में नए उद्योगों को बढावा देना जरूरी है। यह लक्ष्य हम 'मेक इन इंडिया' योजना को बढ़ावा देकर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश बढ़ाने देने की भी जरूरत है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन पहले 54 प्रतिशत युवा आबादी के लिए दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हम युवाओं के 'स्किल डेवलेपमेंट' पर भी जोर दे रहे हैं। हम 'राष्ट्रीय स्किल मिशन' योजना शुरू करने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमें 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' में तालमेल करने की जरूरत है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए फंड की शुरुआत की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले, इससे रोजगार भी बढ़ेंगे।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई प्रावधान किए हैं। स्किल्ड डिवेलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए है।

पिछले साल बजट में सरकार ने कौशल विकास पर जोर दिया था और इस वर्ष मोदी सरकार का 'मेक इन इंडिया' अभियान नौजवानों के लिए एक वरदान साबित होगा। इस अभियान से करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा पर जोर दिए जाने से देश में भारी निवेश होगा जिससे तय अवधि के कॉन्ट्रैक्ट आधारित समेत लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिजली क्षेत्र में निवेश से भी ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है और टेक्नोलॉजी कंपनियों में ठेके पर नियुक्ति का अनुपात बढ़ सकता है।■

भारत एक नौजवान देश है। इसकी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है। नौजवानों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए राजग सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नौजवानों का जीवन बेहतर हो सके, उन्हें रोजगार के उचित अवसर मिले इसके लिए सरकार ने बजट में कई प्रावधान किए हैं।

भूमि अधिग्रहण को लेकर समिति का गठन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह ने 24 फरवरी को भूमि अधिग्रहण पर किसान संगठनों व अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के सुझाव प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित समिति घोषित की है :-

1.	श्री सत्यपाल मलिक	पूर्व केन्द्रीय मंत्री,	संयोजक
2.	श्री भूपेन्द्र यादव	सांसद	सदस्य
3.	श्री रामनारायण ढूढी	सांसद	सदस्य
4.	श्री हुकुमदेव नारायण	सांसद	सदस्य
5.	श्री राकेश सिंह	सांसद	सदस्य
6.	श्री संजय धोत्रे	सांसद	सदस्य
7.	श्री सुरेश अंगडी	सांसद	सदस्य
8.	श्री गोपाल अग्रवाल	सी.ए.	सदस्य

बजट गरीब हितैषी और वृद्धि अनुकूल है : नरेंद्र मोदी

बजट को 'प्रगतिवादी' और 'व्यावहारिक' करार देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह 'गरीब हितैषी' और 'वृद्धि अनुकूल' है और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के अवसर प्रदान करने के साथ ही विदेशी निवेशकों को विश्वसनीय और निष्पक्ष कर प्रणाली का भरोसा भी दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि बजट निवेश और देश की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रावधान करता है ताकि आम आदमी के सपने पूरे हों और रोजगार के अवसर पैदा हों। श्री मोदी ने ट्वीट किया, 'केन्द्रीय बजट 2015 स्पष्ट दृष्टि वाला बजट है। यह एक ऐसा बजट है जो प्रगतिवादी, सकारात्मक, व्यावहारिक और विवेकपूर्ण है।' उन्होंने कहा, 'बजट गरीब समर्थक और वृद्धि समर्थक है..बजट के जरिए हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं।'

उन्होंने इस बात के लिए वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली की सराहना की कि उन्होंने एक ऐसा 'प्रेरणादायी' बजट तैयार किया है, जो गरीबों के लिए है, वृद्धि और रोजगार के लिए है और आम आदमी के सपनों और रोजगार के लिए है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट वृद्धि को नयी जान देगा और विदेशी निवेशकों को स्थिर, विश्वसनीय और निष्पक्ष कर प्रणाली मुहैया कराएगा।

उन्होंने कहा, 'यह बजट हमारी वृद्धि की गाड़ी को नयी रफ्तार देगा और यह एक खुशहाल भविष्य के भोर का संकेत है।' श्री मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री अरूण जेटली को इस गरीब समर्थक, वृद्धि समर्थक, मध्यम वर्ग समर्थक, युवा समर्थक और समूचे परिदृश्य को बदलने वाले बजट के लिए बधाई दी जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, गरीबों और नव मध्यम वर्ग पर खास ध्यान दिया गया है और यह वृद्धि, समानता और रोजगार सृजन पर जोर देता है।

बजट को निवेश हितैषी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह टैक्स मामलों पर तमाम संदेह दूर करता है' और 'निवेशकों को यह भरोसा देता है कि हमारे यहां एक स्थिर, विश्वसनीय और निष्पक्ष कर प्रणाली है।' उन्होंने कहा कि जेटली ने 2022 तक हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों का खाका खींचा है, जिसमें सबके लिए आवास, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पूर्ण बिजलीकरण का प्रावधान है।

काले धन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक नया कानून बनाने की बात करना विदेशों में पड़े काले धन का एक-एक रुपए वापस लाने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि बजट इस बात का भी संकेत देता है कि सरकार भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों के लिए विकास की भागीदारी सुनिश्चित करने और भविष्य में वृद्धि की दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाने के लिए भी वचनबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जन-धन योजना की सफलता हर्षित करने वाली है और इसी पर आगे बढ़ते हुए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिससे गरीबों के जीवन में समूल बदलाव आएगा।

इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने नयी योजनाओं जैसे सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम का ऐलान किया और कहा कि इससे जन-धन से जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा।

उन्होंने कहा कि अटल नवाचार मिशन और सेतु जैसी योजनाएं भारत में नवाचार, उद्यमिता और नवागन्तुकों को बढ़ने और निखरने का मौका देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। ■

'गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को समर्पित बजट'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आम बजट 2015-16 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सबका बजट है। इस बजट में गरीबों के विकास, युवाओं को शिक्षा व रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, राज्यों की समृद्धि बढ़ाने और अर्थव्यवस्था मजबूती देने वाला बजट है।

- गरीबों को स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा देने वाला बजट, एक रुपये प्रतिमाह के प्रीमियम पर होगा दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
- सबको पेंशन की सुरक्षा देने वाला बजट, अटल पेंशन योजना की शुरुआत
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत होगा दो लाख रुपये का बीमा, एक रुपये प्रतिदिन से भी कम जाएगा प्रीमियम
- ईपीएफ, जीपीएफ में पड़ी दावारहित 9000 करोड़ रुपये होगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना
- किसानों के लिए नई परंपरागत कृषि विकास योजना
- निर्भय फंड के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन
- प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की होगी शुरुआत
- युवाओं के लिए शोध और अनुसंधान को बढावा देने को 150 करोड़ रुपये अटल इनोवेशन योजना
- SC, ST & OBC के युवा उद्यमियों के लिए मुद्रा बैंक व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 23000 करोड़ रुपये आवंटित
- दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
- बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए भी आंध्र प्रदेश की तरह विशेष सहायता
- मिड डे मील के लिए 68968 करोड़ रुपये आवंटित
- नमामि गंगे के लिए 4173 करोड़ रुपये
- युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया
- विवादास्पद GAAR का क्रियान्वयन दो साल के लिए टाला
- कालेधन पर लगाम लगाने वाला बजट
- घरेलू और विदेशी कालेधन
- मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन
- सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत बालिकाओं के लिए धारा-80सी के तहत कर लाभ
- कालेधन पर जुर्माना कर देनदारी का 300 प्रतिशत लगाया जायेगा,
- कर चोरी करने वाले मामलों सुलझाने के लिए निपटान आयोग में नहीं जा सकेंगे
- कालाधन छिपाने पर 10 साल तक की कैद होगी
- विदेशी सम्पत्तियों को छिपाने वालों को जेल की कठोर सजा सहित कर चोरी के खिलाफ और सख्त होंगे कानून
- व्यक्तिगत करदाताओं को सालाना 4 लाख 44 हजार 200 रुपये की आय पर विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट उपलब्ध होगी
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर आयकर कटौती की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रस्ताव
- बुजुर्गों के मेडिकल खर्च पर 30 हजार रूपये तक कर कटौती
- मनरेगा के लिए प्रारंभिक प्रावधान 34,699 करोड़ रूपये। सरकार की आय बढ़ने पर पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन होगा
- सम्पत्ति कर समाप्त, एक करोड़ रूपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार
- रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रुपये
- किसानों को 8.5 लाख करोड़ रूपये कृषि ऋण देने का लक्ष्य
- छोटे कारोबारियों की ऋण सुविधा के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के कोष से मुद्रा बैंक बनाया जायेगा
- अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'मंजिल' योजना. अल्पसंख्यक मंत्रालय को 2015-16 के लिए 3738 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजग सरकार के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2015-16 सबका

बजट है। इस बजट में गरीबों के विकास, युवाओं को शिक्षा व रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, राज्यों की समृद्धि बढ़ाने और अर्थव्यवस्था मजबूती देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि राजग सरकार गरीबों को समर्पित है। इसलिए इस बजट में गरीबों को आजीविका से लेकर, स्वास्थ्य , दुर्घटना और जीवन बीमा का तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के रूप में गरीबों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के बाद सरकार ने अब सबको पेंशन और बीमा की सुरक्षा देने की घोषणा की है। इसके अलावा किसानों के लिए प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना शुरु करने के साथ ही कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। सरकार ने युवाओं को कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के समुचित अवसर मुहैया कराने के लिए आम बजट में भारी भरकम धनराशि आवंटित करने के साथ-साथ देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कई उपायों का ऐलान किया है। इसके तहत कार्पोरेट कर में कमी की गई है ताकि अधिकाधिक संख्या में उद्योग भारत में निवेश के लिए आकर्षित हों जिससे देश के युवाओं को रोजगार और अच्छी नौकरियां मिलें। साथ ही सरकार ने राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को घटाकर जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर पर लाने की घोषणा भी की है।

सरकार का यह बजट काले धने पर कठोर लगाम लगाने वाला बजट है। इसलिए सरकार ने देश के बाहर और भीतर जमा कालेधन को निकालने के लिए आम बजट में ठोस उपाय किए हैं। सरकार कालेधन की समस्या के निदान के लिए फेमा के अंदर परिवर्तन करेगी जिसके बाद विदेश में कालाधन रखने वालों को सात से दस साल तक के कठोर कारावास की सजा भी दी जा सकेगी। विदेश में जमा कालेधन का ब्यौरा न देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वी राज्यों के विकास का वादा किया था। इसलिए राजग सरकार ने आम बजट में बिहार और पश्चिम बंगाल में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगों को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर विशेष सहायता देने की घोषणा की है।

इस तरह राजग सरकार का यह पहला पूर्ण आम बजट देश को तरक्की राह पर लाने और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के सपने को साकार करने वाला बजट है। ■

पृष्ठ 9 का शेष...

भाजपा' या यों कहें कि हर घर में भाजपा का एक सदस्य, जो पार्टी का अन्तिम उद्देश्य है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, जिन्होंने 1000 से अधिक सदस्य बनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सुन्दरा-राजन और केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन ने जनसभा को सम्बोधित किया।

अन्य लोगों में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव, भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री एच. राजा, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सी.पी. राधाकृष्णन और राज्य सचिव श्री जी.के.एस. सेल्वाकुमार उपस्थित थे।

भाजपा सदस्यता अभियान की विशेषताएं

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 नवम्बर 2014 को की ताकि भाजपा में 3-4 गुणा अधिक प्राथमिक सदस्य बनाए जा सकें।
- पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत एक नए विजन, संकल्प और 'सशक्त भाजपा, सशक्त भारत' नारे के साथ की।
- सदस्य बनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति भाजपा में प्राथमिक सदस्य बनने के लिए 18002662020 पर फोन कर सकता है।
- जिन व्यक्तियों के पास मोबाइल नहीं हैं, वे 9242492424 पर फोन करें और वह भाजपा का सदस्य बन सकता है।
- जो सक्रिय सदस्य बनना चाहते है तो उन्हें किसी ऐसे इलाके, मलिन बस्ती, दलित बस्ती, गांव या ब्लॉक में 7 दिन काम करना होगा, जहां भाजपा का कोई सदस्य नहीं है और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- सक्रिय सदस्य बनने के लिए कम से कम 100 प्राइमरी सदस्य बनाना अनिवार्य है।
- जब से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है तब से अब तक लगभग 6.36 करोड़ सदस्य बन चुके हैं।
- वर्तमान सदस्यता अभियान 31 मार्च 2015 तक चलेगा।
- 31 मार्च के बाद संगठन ने पूरे वर्ष 2015 को 'सदस्यता पर्व वर्ष' मनाने का निर्णय लिया है।
- 'सदस्यता पर्व वर्ष' मनाने का उद्देश्य है कि देश के हर घर तक पहुंचा जाए और पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि 'घर घर भाजपा' या देश के प्रत्येक घर से भाजपा का एक सदस्य बने। ■

रेल बजट 2015-16

आम लोगों को राहत देने वाला है रेल बजट

संवाददाता द्वारा

केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने संसद में 26 मई को रेल बजट 2015-16 प्रस्तुत किया। सही अर्थों में यह रेल बजट भारतीय रेल का पुनर्जन्म है। इस रेल बजट की खास बात रही कि यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके साथ ही, रेल संसदीय इतिहास में शायद पहली बार किसी रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा नहीं की गई। यह स्पष्ट संकेत था कि रेलवे अब राजनीतिक तुष्टीकरण का औजार नहीं बनेगी। बजट में यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और अधोसंरचना को बेहतर बना रेलवे को एक मजबूत आधार देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन की स्पष्ट छाप लिए श्री प्रभु के इस बजट में यात्रियों के लिए कई सौगातें हैं।

रेल बजट की मुख्य बातें

- यात्री रेल किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ेगा।
- 60 दिन के बजाय अब 120 दिन पहले की जा सकेगी टिकट की बुकिंग, पेपरलेस टिकटिंग पर जोर।
- नई ट्रेनों का अभी ऐलान नहीं, समीक्षा चल रही है, इसी सत्र में होगा ऐलान।
- राजधानी और शताब्दी समेत सभी ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाई जाएगी, भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में और डिब्बे जोड़े जाएंगे
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ की सीटें अधिक आरक्षित होंगी।
- रेलवे में अब सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे।
- 400 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा, 10 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन विकसित होंगे।
- 970 रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे, 3438 मानवरहित क्रॉसिंग खत्म किए जाएंगे।
- 4 रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय चेयर फॉर रेलवे टेक्नोलॉजी की घोषणा।
- इस्तेमाल करो और फेंको श्रेणी के बिस्तर सभी स्टेशनों पर भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- कई भाषाओं में होगी ई-टिकटों की बुकिंग, अनारक्षित टिकटों की बुकिंग ऐप्लिकेशन के जरिए मुमकिन।
- जल्द टिकट बुकिंग के लिए ऑपरेशन फाइव मिनट।
- अब खाने का ऑर्डर ऑनलाइन भी कर सकेंगे।
- शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एस्कलेटर्स, ऑनलाइन व्हीलचेयर्स, बड़े प्रवेश द्वार की सुविधा।
- 17 हजार बायो टॉयलेट्स बनाए जाएंगे।
- वेंडिंग मशीन के जरिए सस्ता और शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा।
- उपनगरीय इलाकों में सेटेलाइट स्टेशन बनाए जाएंगे।
- ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान की जानकारी अब एसएमएस के जरिए भी।
- कुछ स्टेशनों पर पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी भुगतान लेकर दी जाएगी।
- इसरो की मदद से ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए वार्निंग प्रोटेक्शन प्रणाली को अपनाई जाएगी। ■

भाजपा अध्यक्ष की टिप्पणी

यह रेल बजट 'यात्री बजट' है : अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट भविष्योन्मुखी, विकासोन्मुखी और 'यात्री बजट' है। राजग सरकार ने रेल बजट 2015-16 में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं व सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने को कई अभिनव उपायों की घोषणा की है। राजग सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति को चरितार्थ करते हुए रेल बजट की प्रमुख विशेषता यह है कि यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी। इतना बेहतरीन रेल बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु को बहुत-बहुत बधाई और अभिनंदन।

रेल मंत्री ने यात्रियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए रेल बजट में दर्जनों ऐसे उपाए किए हैं जिससे यात्रियों का सफर सुहाना होगा। रेल बजट में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं के धन आवंटन में 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यात्रियों की शिकायतों के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर 138 शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही रेल शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा। यह 1 मार्च, 2015 से उत्तर रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा संबंधी शिकायतों के लिए टॉल फ्री नंबर 182 भी शुरु किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि राजग सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। इसलिए रेल बजट में ऐसे कई उपाय किए गए हैं जिससे गरीब यात्रियों को सहूलियत होगी। उदाहरण के लिए अनारक्षित टिकट खरीदने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए

रेल मंत्री ने गिनाए रेलवे के पांच लक्ष्य

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए रेलवे के 5 लक्ष्य गिनाए। उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू करने से पहले रेलवे का महत्व बताते हुए कहा, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने से पहले रेल के जरिए ही देश को जाना था।

श्री प्रभु ने कहा, रेलवे का पहला लक्ष्य सुविधा बढ़ाना, दूसरा सुरक्षा बढ़ाना, तीसरा क्षमता बढ़ाना, चौथा रेलवे को आत्मनिर्भर बनाना और पांचवा रेलवे में निवेश बढ़ाना है। श्री सुरेश प्रभु ने अगले पांच साल में रेलवे में 8.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य बताया।

रेल मंत्री ने कहा, निवेश में कमी के कारण रेलवे की क्षमता, सुरक्षा और सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा सकीं। उन्होंने रेलवे की बुरी हालत बताते हुए कहा, स्थिति ऐसी है कि एक ही ट्रैक पर शताब्दी भी चलानी पड़ती है, पैसेंजर ट्रेन भी चलानी पड़ती है और मालगाड़ी भी चलानी पड़ती है।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, रेलवे की स्थिति से वह खुद भी असमंजस में आ जाते हैं और कई बार कहते हैं, 'हे प्रभु! ये कैसे होगा?' उनके ऐसा कहते ही सदन में ठहाके गूंज उठे।

रेल मंत्री का कहना था कि रेलवे में रातों-रात सब कुछ नहीं बदला जा सकता है, इसे करने में समय लगेगा। इसके लिए बहुत कुछ बदलना होगा, नए रास्ते बनाने होंगे। उन्होंने कहा, बजट में हमने लोगों के सुझाव भी शामिल किए हैं। सुरेश प्रभु ने कहा कि उनका प्रमुख लक्ष्य सुरक्षा और आधारभूत ढांचा ठीक करना है। श्री सुरेश प्रभु का कहना था कि अगले 5 साल में रेलवे का कायाकल्प होगा। इसके साथ ही उन्होंने विजन 2030 भी पेश करने की बात कही। उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर सुविधा बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों से साझीदारी करने की बात भी कही।

'ऑपरेशन 5 मिनट' शुरू होगा ताकि अनारक्षित टिकिट खरीदने में पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लगे। प्रारंभिक तथा गंतव्य स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की जानकारी देने के लिए एसएमएस अलर्ट की सुविधा होगी, जो गाड़ी के आने से 15 से 30 मिनट पहले भेजा जाएगा। इसके साथ सभी प्रमुख स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा मिलेगी। सामान्य श्रेणी के डिब्बों में भी मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ट्रेन आने या रवाना होने से पहले एसएमएस अलर्ट की सुविधा होगी। इसके अलावा फोन पर अनारक्षित टिकिट भी खरीदा जा सकेगा। युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से रेलवे कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी मुहैया कराएगा।

राजग सरकार ने रेल बजट में मध्यम वर्ग की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है। टिकट बुकिंग के लिए भी समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इससे टिकट बुकिंग में दलालों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए लोअर बर्थ में उनका कोटा बढ़ाया जाएगा साथ ही टीटीई को यह निर्देश दिया जाएगा कि वे वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ दिलाने में मदद करें। यात्रियों को बेहतरीन खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ई-केटरिंग के तहत सर्वोत्कृष्ट खाद्य चेन की शुरुआत करेगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए चल टिकट परीक्षकों (टीटीई) को हैंड हैल्ड टर्मिनल उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका उपयोग यात्रियों का सत्यापन और चार्टो को लाउनलोड करने के लिए किया जा सकेगा। इससे रेलवे को टिकिटिंग और चार्ट तैयार करने में कागज का इस्तेमाल न करने तथा रिफंड के दावों को अंतिम रूप देने में भी तेजी लाने में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर रेलवे में साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया है। 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' मिशन के तहत स्टेशनों और गाड़ियों की सफाई के लिए एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जिसमें प्रोफेशनल एजेंसियों की सेवाएं लेना और अपने कर्मचारियों को साफ सफाई की नवीनतम पद्धति का प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल होगा। स्टेशनों और गाड़ियों में शौचालय सुविधाओं की हालत में सुधार किया जाएगा। पिछले वर्ष के 120 स्टेशनों की तुलना में 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नए शौचालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस वर्ष 17 हजार और जैव शौचालयों लगाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेनों में बेड लिनेन की संरचना, गुणवत्ता और साफ सफाई भी सुधारी जाएगी।

- राजग सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट ''यात्री बजट''
- रेल बजट सबका साथ सबका विकास की नीति का परिचायक
- भारतीय रेल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर
- राजग सरकार गरीबों के लिए समर्पित
- मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा रेल
- सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल
- रेलवे की क्षमता बढाना और आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख लक्ष्य
- यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं
- यात्री सुविधाओं के लिए 67 प्रतिशत की वृद्धि
- 200 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने का लक्ष्य

रेल बजट में यात्रियों की सुविधाओं के साथ-साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चुनिंदा रूट पर ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम एंड ट्रेन कॉलाइजन अवोइडेंस सिस्टम लगाया जाएगा। 3438 मानवरहित क्रॉसिंग के लिए 6581 करोड़ रुपये का प्रावधान। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे निर्भय फंड का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बुलेट ट्रेन के डायमंड क्वालड्रीलेटरल के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेल बजट में हाईस्पीड ट्रेन के लिए अगले पांच साल के लिए भारी भरकम 65,000 करोड़ रुपये का आवंटन किए गए हैं। साथ ही मुंबई और अहमदाबाद के बीच उच्च रफ्तार की रेल गाड़ियां चलाने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन रिपोर्ट इस वर्ष के मध्य तक तैयार हो जाएगी।

भारतीय रेल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि सरकार ने रेल बजट में इसके लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। उदाहरण के लिए रेलवे का योजनागत आवंटन 52 प्रतिशत वृद्धि के साथ बढ़ाकर

1,00,011 करोड़ रुपये किया गया है। वित्त मंत्रालय रेलवे को 40,000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता मुहैया कराएगा। इस तरह अगले पांच साल में रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था का वाहक बनेगा। रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए रेलवे अपनी भूमि के मानचित्रों को डिजिटाइज करेगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।

रेलवे में उत्कृष्ट मानव विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अवधारणा को साकार करते हुए रेल बजट में वर्ष 2015-16 में पूर्ण विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा भी की कई है।

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय रेलवे के कायाकल्प हेतु अगले पांच वर्षों के लिए चार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य ग्राहकों के अनुभव में स्थायी और मापन योग्य सुधार लाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा ऐसे कदम जाएंगे जिनसे स्वच्छता, सहूलियत, सुगमता, सेवा गुणवत्ता और गाड़ियों की गति से संबंधित ग्राहकों की समस्याएं व्यवस्थित ढंग से दूर हो जाएंगी। दूसरा लक्ष्य रेलवे को यात्रा का सुरक्षित साधन बनाना, तीसरा लक्ष्य भारतीय रेलों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करना और इसकी अवसंरचना को आधुनिक बनाना। नागरिकों के लिए रेल यात्रा के महत्व को देखते हुए, भारतीय रेलवे यात्री वहन क्षमता 21 मिलियन यात्री प्रति-दिन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक करेगा। रेलपथ की लंबाई भी 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर 1,14,000 कि.मी. से 1,38,000 कि. मी. तक की जाएगी। चौथा लक्ष्य वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए भारतीय रेलवे परिचालन से अत्याधिक अधिशेष का सृजन करेगा, जो केवल क्षमता विस्तार के वित्तपोषण हेतु आवश्यक ऋण की अदायगी के लिए ही नहीं होगा, बल्कि उससे क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को सतत आधार पर बदलने हेतु निवेश के लिए भी पर्याप्त होगा। रेल बजट में आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी में रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए 'मालवीय पीठ' स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। रेल मंत्री ने वर्ष 2015-16 के लिए 88.5% के परिचालन अनुपात का प्रस्ताव रखा है। जबकि 2014-15 में परिचालन अनुपात का लक्ष्य 91.8% तथा 2013-14 में 93.6% रखा गया था। इस तरह यह बजट न केवल पछले 9 वर्ष का बल्कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद का भी सर्वोत्तम परिचालन अनुपात वाला बजट होगा। ■

'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' मिशन के तहत स्टेशनों और गाड़ियों की सफाई के लिए एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जिसमें प्रोफेशनल एजेंसियों की सेवाएं लेना और अपने कर्मचारियों को साफ सफाई की नवीनतम पद्धति का प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल होगा। स्टेशनों और गाड़ियों में शौचालय सुविधाओं की हालत में सुधार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश

झूठ पर आधारित है सपा सरकार का बजट : लक्ष्मीकांत वाजपेयी

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सपा सरकार जिस विकास दर की बात रही है, उसके कार्यकाल में यह साल-दर-साल घट रही है। उन्होंने कहा कि 2012-13 में विकास दर 5.8 प्रतिशत, 2013-14 में 5 प्रतिशत, जबकि देश की विकास दर 6.9 प्रतिशत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश सरकार के पहले बजट में राज्य सेक्टर का मात्र 49 प्रतिशत बजट का पैसा अवमुक्त हुआ था और जिला योजना का 14 प्रतिशत बजट पैसा अवमुक्त हुआ था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में 9 माह बीतने के बाद भी बजट को खर्च करने में सरकार विफल रही है। इसके साथ ही भाजपा ने 2015-16 को किसान वर्ष मनाने की घोषणा पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष गेहूं और धान के खरीद केंद्रों से एक दाना भी नहीं खरीदा। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के भुगतान का बकाया, उसके समर्थन मूल्य को नहीं बढ़ाना, आलू किसानों की दुर्दशा, घोषणा-पत्र के अनुसार तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कृषि मूल्य आयोग का गठन न कर पाना, खाद की कमी, कालाबाजारी, सिंचाई के लिए रजवाहों में टेल तक पानी न आना, सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध न होना, नकली बीज भी किसानों के साथ हुए धोखे और किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा भी किसाने के साथ धोखा है। ■

संसद में बहस

मेरी सरकार का एक ही धर्म 'इंडिया फर्स्ट' : नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को लोक सभा में धन्यवाद प्रस्ताव रखा। श्री मोदी अपने भाषण में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार का कारपोरेट के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए काम कर रही है। हम उनके भाषण का सारांश यहां प्रकाशित कर रहे हैं:-

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष के सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने विषय रखे हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण में देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, किस दिशा में हो रहे हैं और किस गति से हो रहे हैं, उनका उल्लेख किया है। योजना नयी है, पुरानी है, इसके ऊपर तो विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि समस्या पुरानी है। इसलिए हमें जो समस्यायें विरासत में मिली हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के रास्ते हम खोज रहे हैं। ऐसे विषयों पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। वर्ष 1999 में अटल जी ने टोटल सैनिटेशन का प्रोजेक्ट लगाया था। क्या निर्मल भारत उसी योजना का दूसरा नाम था? मैं समझता हूं कि मुद्दा समस्या है, नाम मुद्दा नहीं है। स्वच्छता हमारी मानसिकता से ज्यादा जुड़ी हुई है। गन्दगी के कारण जो बीमारी फैलती है, उस वक्त एक गरीब पर सात हजार रुपए का खर्च आता है। स्वच्छता का दूसरा संबंध नारी के सम्मान के साथ है। उनको सम्मानित जीवन जीने का एक अधिकार देने का है। बालिकाएं स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि स्कूल में गर्ल चाइल्ड टॉयलेट नहीं हैं।

इसलिए स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाया है। जन सामान्य स्वच्छता के काम को पसन्द करता है। स्वच्छता को लेकर टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया तो हमें लोगों ने 400 करोड़ रुपये दिये। यह काम सवा सौ करोड़ देशवासियों का है। सरकारों आती हैं, जाती हैं। सरकारें देश नहीं बनातीं, देश जनता-जर्नादन की सामर्थ्य से बनता है। राष्ट्र अपनी फिलॉस्फी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें समस्याओं का समाधान खोजना है, यहां मंथन करके रास्ते खोजने हैं। कभी-कभार यह कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना विश्वास जरूर करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्षमता के विषय में शक होगा। लेकिन एक विषय में आप जरूर मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझ-बूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझ-बूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता-जागता स्मारक है। आजादी के साठ साल बाद आपको लोगों के गड्ढ़े खोदने के लिए भेजना पड़ा। यह आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा।

दुनियां को बताऊंगा कि ये गड्ढ़े जो आप खोद रहे हैं, उन साठ साल के पापों का परिणाम है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रख दिया है। देश में भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करें। हम मिलकर यह तय

करें कि इसे आगे नहीं होने देंगे तभी भ्रष्टाचार जा सकता है। पॉलिसी ड्रिवेन स्टेट चलाएं जब नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। उदाहरण के तौर पर कोयले का आबंटन, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट लिखने वालों को भी लगता है कि इतना तो नहीं हो सकता। लेकिन 1,86,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार, इस पर देश भी चौंक गया था। जब कोयले का आबंटन हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया। अभी तक 18 या 19 ऑक्शन ही हुए हैं। उनमें करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आ चुका है। जब 204 ऑक्शन हो जाएंगी तब सीएजी ने जो सोचा था, उससे भी बड़ी इस ऑक्शन से आने वाली है। यह सीधा-सादा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। काले धन की चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर एस॰आई॰टी॰ बनाने के लिए कहा था।

जब कोयले का आबंटन हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया। अभी तक 18 या 19 ऑक्शन ही हुए हैं। उनमें करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आ चुका है। जब 204 ऑक्शन हो जाएंगी तब सीएजी ने जो सोचा था, उससे भी बड़ी इस ऑक्शन से आने वाली है।

तीन साल तक एस॰आई॰टी॰ नहीं बनायी गई। नयी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय काले धन पर एस॰आई॰टी॰ बनाने के लिए किया। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया और स्विटजरलैंड गवर्नमैंट को हमें महत्वपूर्ण जानकारियां एक्सचेंज करने के लिए राजी कर लिया। हमने जी-20 का क्या उपयोग किया? जी-20 समिट के अंदर जो संयुक्त डेक्लरेशन हुआ, उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैकमनी, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जी-20 को जिम्मेदारी के साथ कदम उठाना चाहिए। हम वायदा करके आये हैं। वह व्यक्ति, जरूरी नहीं कि सब राजनेता हो, लेकिन जिसने भी किया है, देश का तो नुकसान किया ही है। इसलिए उस संबंध में सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, हमारी है। सरकार के प्रयास होने चाहिए, हम कर रहें हैं और अंतिम विजय प्राप्त करने तक करते रहेंगे, यह मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं।

हम एक तरफ किसान की बहुत बात करते हैं लेकिन किसान को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए रास्ता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? कई उपाय हैं। जैसे हम काम लेकर निकले हैं - पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हमारे देश में पानी की कमी है। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के भविष्य को देखकर कुछ बातें करें? हमने सॉएल हैल्थ कार्ड की बात कही है। हमने मंत्र दिया है - स्वस्थ धरा तो खेत हरा। क्यों न हम गांव-गांव सॉएल टैस्टिंग लैब के लिए एन्टरप्रियोनर तैयार करें? गांव के नौजवान जो थोड़े बहुत पढ़े-लिखे हैं, उनको ट्रेनिंग दें। मैंने स्कूलों में छुट्टियों के दौरान स्कूलों की प्रयोशालाओं को सॉएल टैस्टिंग लैब के रूप में बदलने के लिए कहा है। इससे स्कूल को तो इंकम होगी ही और गांव के नौजवानों को भी इंकम होगी। हमें अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इसे सुशासन कहते हैं। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित है। हमने अनाप-शनाप खर्चे कम करने के लिए व्यय आयोग बनाया है ताकि इससे जो बचत हो वह पैसा गरीबों के कल्याण के काम आए। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं। हम लाल फीताशाही को कम करना चाहते हैं ताकि सामान्य मानवों को कोई असुविधा न हो और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं जिसका लाभ शीघ्र ही सामने आने लगेगा। मैं जापान गया, वहां एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साइंटिस्ट यामानाका को मिलने गया उन्होंने स्टेम सेल के अंदर रिसर्च की है। मेरे मन में आया था कि शायद इनकी यह खोज हमारे काम आ सकती है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे देश के आदिवासियों को परम्परागत रूप से स्किल-सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। स्किल-सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं अभी तक उसकी कोई दवा नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम-सेल के द्वारा स्किल-सेल बीमारी से मुक्ति हो जाए। बैंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीटयूट के साथ आज उस दिशा में काम हो रहा हैं। हम आस्ट्रेलिया जी-20 सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां मैं उन कृषि वैज्ञानिकों से मिलने उनके लैब में गया जिन्होंने प्रति हेक्टेयर चना ज्यादा उगाने का सफल प्रयोग किया था। हम दालों के मामले में बहुत पीछे हैं। अगर हमारा किसान प्रति हेक्टेयर ज्यादा दालें पैदा कर सकता है तो उसको भी अच्छी आय मिलेगी और हमारे गरीब लोगों का ही भला होगा। मैं एक अन्य वैज्ञानिक के पास गया, उन्होंने केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई हैं केला गरीब

का फल होता है। अगर केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है तो मेरे देश का गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। देश का गरीब, आदिवासी और किसान हमारे दिमाग में होता है। यहां पर जन-धन योजना को लेकर कहा गया कि यह तो हमारे यहां हर समय थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए 40 साल हो गए लेकिन आज भी इस देश का गरीब बैंक के दरवाजे से दूर था। हमने पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया था कि 26 जनवरी को इस योजना के तहत खाते खोलने का काम पूरा करेंगे और हमने समय के रहते काम पूरा किया है। अब हम मनरेगा का पैसा भी जन-धन योजना के तहत देंगे, इससे लीकेज़ कम से कम हो जाएगा और पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। मैं जब शौचालय की बात कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीब सवा चार लाख शौचालयों की स्कूलों में जरूरत है। इनमें से डेढ़ लाख के करीब नए शौचालय बनाने पड़ेंगे और बाकी शौचालयों को रिपेयर करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है सारी डिटेल वर्कआउट की गई है। कई माननीय सदस्यों ने इस काम को सक्रियता से किया है। अपने इलाके में एम॰पी॰ लैड फंड का भी उपयोग किया है। मुझे विश्वास है कि स्कूलों में जून महीने में जब नया सत्र शुरु होगा, उसके पहले टॉयलेट बनाने का काम पूरा हो जाएगा। स्वच्छता अभियान का पर्यटन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमने ऑनलाइन ''अराइवल ऑन वीज़ा'' शुरु किया हैं इन दोनों का संयुक्त प्रभाव पर्यटन पर पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में पर्यटन में बहुत अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसी कौन सी सरकार होगी जिसके समय में आपदा नहीं आई है। लेकिन आपदा प्रबंधन के तरीके भी बदले जा सकते हैं। जब जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई, तो मैंने पहला काम यह किया कि भारत सरकार में जम्मू-कश्मीर के जितने अधिकारी हैं, पहले उनकी सूची बनाओ। उस समय के होम सेक्रेटरी जो जम्मू-कश्मीर कैडर के थे, उन्हें मैंने वहां भेज दिया और हफ्ते भर वहां रखा। हमें पूरी ताकत से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ता है। मैं स्वयं कश्मीर गया और कितने ही ग्रुपों के साथ मैंने बारीकी से बातें की। यहां पर भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर बढ़िया बातें मैं सुन रहा हूं। जब यह अधिनियम बना था तब हम भी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको पारित करने के लिए खड़े रहे थे। कानून बनने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक आवाज़ से कह रहे थे कि किसानों के लिए कुछ सोचिए। एक तरफ तो यह देश फैडरल कोआपरेशन की बात करता है, और दूसरी तरफ अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात को नहीं सुनें? क्या हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए और उनकी भावना का आदर नहीं करना चाहिए? मुझे सेना के अधिकारी मिले। वे कहते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण विद्यमान कानून हैं, उसके तहत डिफेंस इंस्टालमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है वह संभव नहीं हो पाएगा। अगर विद्यमान कानून में कोई गलती रह गई है तो उसे ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे को मैंने सभी विभागों के साथ जोड़ दिया है। मैंने कहा है कि सब विभागों के साथ मिल कर काम करो। सभी राज्यों के साथ मिल कर काम करो। हमने विकास की उस परिभाषा को ले कर चले थे। इसलिए मैं कोऑपरेटिव फेड्रलिज्म की बात करता हूं। क्योंकि उन राज्यों की समस्याओं को हमें एड्रेस करना चाहिए। उसने यह किया, वह किया, नहीं किया, उसके आधार पर देश नहीं चलता है। देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देश को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध और सशक्त बनाना है। हमने आते ही ये खनिज रॉयल्टी वगैरह डेढ़ गुना कर दिया। वह पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। वे राज्य कौन हैं?

गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। देश का गरीब, आदिवासी और किसान हमारे दिमाग में होता है। यहां पर जन-धन योजना को लेकर कहा गया कि यह तो हमारे यहां हर समय थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए 40 साल हो गए लेकिन आज भी इस देश का गरीब बैंक के दरवाजे से दूर था। हमने पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया था कि 26 जनवरी को इस योजना के तहत खाते खोलने का काम पूरा करेंगे और हमने समय के रहते काम पूरा किया है।

जहां सबसे ज्यादा हमारे देश के पूर्वी इलाके में है। वहां उनको लाभ होने वाला है। कोयला ऑक्शन हुआ, उसका पैसा किसको जाएगा? यह सारा का सारा पैसा उनके सामने पड़ा होगा। क्या यह फेड्रल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है या नहीं है? अभी हमने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर के राज्यों को 42 पर्सेंट दे रहे हैं। जब कि

फाइनेंस कमीशन एकमत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मैंबर्स के अंदर भी डिस्प्यूट हैं। हम उसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन हम नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि तत्वत: हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। इसलिए हम 42 पर्सेंट दे रहे हैं। यह अमाउंट छोटा नहीं है। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास जो खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल अगर लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा कि 62 पर्सेंट खजाना राज्यों के पास है और केवल 38 पर्सेंट खजाना भारत सरकार के पास है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमें ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए। उस काम को हम कर रहे हैं और राजनीति से परे हो कर कर रहे हैं। हमारे देश में राजनीतिक कारणों से सांप्रदायिकता का जहर घुलता जा रहा है। यह आज से नहीं चला आ रहा है, यह लंबे अरसे से चला आ रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। यह देश विविधताओं से भरा हुआ है।

विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एकरूपता के पक्षकार नहीं हैं, हम एकता के पक्षकार हैं और सभी संप्रदायों का फलना-फूलना भारत की धरती पर ही संभव होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वह संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। वह हमारे भारत के सामान्य मानविकी, आशा, आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने वाला संविधान है और इस संविधान की मर्यादा में रहकर ही देश चल सकता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं सरकार में बैठा हूँ, सरकार कैसे चलेगी उसकी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट क्या है। मैंने बार-बार कहा है कि मेरी सरकार का एक ही धर्म है इंडिया फर्स्ट।

मेरी सरकार का एक ही धर्म है भारत का संविधान, मेरी सरकार का एक ही धर्मग्रंथ है, भारत का संविधान, मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति, मेरी सरकार की एक ही पूजा है, सवा सौ करोड़ देशवासियों का कल्याण, मेरी सरकार की एक ही कार्य शैली है, सबका साथ-सबका विकास। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि सबका साथ- सबका विकास, तो यह सबका साथ-सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए क्योंकि सबका विकास करना है। ■

बिहार

भूमि अधिग्रहण में किसान विरोधी क्या है : सुशील मोदी

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने 9 मार्च को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करने वाले जदयू नेताओं से सवाल पूछा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह बताने को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में किसान विरोधी ऐसा क्या है।

श्री मोदी ने कहा कि किसान के हितों पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि राज्य के हजारों किसानों को औने-पौने दामों पर अपना धान क्यों बेचना पड़ा? धान खरीद शुरू हुए चार महीने बाद भी तय लक्ष्य 30 लाख टन की जगह मात्र 11 लाख टन की ही खरीद क्यों हो पायी है? कृषि रोड मैप बिहार में बुरी तरह विफल क्यों हो गया? श्री सुशील मोदी ने कहा कि भू-अर्जन के नये कानून में शहरीकरण के लिए ली जानेवाली जमीन में मुआवजे के अतिरिक्त जमीन मालिक की हिस्सेदारी विकसित भूमि के 20 प्रतिशत हिस्से में होगी। जिस परियोजना के कारण रोजगार पैदा होगा, उसमें जमीन देने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी या पांच लाख रुपया प्रति परिवार या दो हजार रुपया 20 साल तक प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। विस्थापित परिवारों को 50 हजार रुपया परिवहन तथा 50 हजार रुपया पुनर्वास भत्ता के तौर पर देय होगा।

श्री मोदी ने कहा, भूमि अधिग्रहण के नये कानून में गांव, किसान और गरीबों के हितों को प्राथमिकता देते हुए केवल प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसमें न केवल किसानों की सहभागिता बढ़ेगी, बल्कि पैदा होनेवाले रोजगार का प्रत्यक्ष लाभ भी उन्हें मिलेगा। इस कानून का विरोध करनेवाले नीतीश कुमार न केवल जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, बल्कि अपने विकास विरोधी चरित्र को भी उजागर कर रहे हैं। ■